भाजपा-रालोपा विधायकों ने विधानसभा में उठाई रीट की सीबीआई जांच की मांग

विपक्ष के विधायकों ने काली पट्टी बांधकर और तख्तियां लहराकर विरोध जताया

जयपुर, (वि.सं.) विधानसभा शुरू होते ही भाजपा और रालोपा विधायकों ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक के मुद्दे पर घेर लिया। सदन में विपक्ष के विधायक हाथों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और

- रालोपा के तीन विधायकों ने अभिभाषण के बीच ही वैल में आकर नाराजगी जताई, इसके बाद वाक आउट कर गये
- राज्यपाल ने विरोध कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी

सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन में तख्तियां लहराई। वहीं आरएलपी विधायकों ने अभिभाषण के दौरान करीब 15 मिनट तक वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद वे सदन से वाकआउट कर गये।

भाजपा के विधायक और रालोपा के तीनों विधायक "रीट की सीबीआई जांच हो" लिखी तख्तियां थामे सदन में आये और अभिभाषण के शुरु होते ही तख्तियां सामने करके अपनी जगह पर खड़े हो गए। भाजपा सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल व उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित सभी विधायकों ने तख्तियां लहराई। रालोपा विधायक नारायण बेनीवाल सहित पार्टी के तीनों विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग और इंद्रा देवी रीट परीक्षा मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराते हुए वेल में आ गये और इस मांग के समर्थन में बोलते रहे। करीब पन्द्रह मिनट बाद तीनों विधायक सदन से बहिर्गमन कर गए जबकि भाजपा के सदस्य अपनी जगह पर पूरे अभिभाषण में खड़े रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विरोध कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि आप बैठ जांएगे तो अच्छा लगेगा, सदन चलता रहेगा, आप डटकर विरोध करना लेकिन विरोध कर रहे सदस्य अपनी जगह पर पूरे अभिभाषण के दौरान खड़े रहे। अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे की सीट की तरफ आये और कहा कि बैठकर भी तख्ती दिखा देते तो हम विरोध मान लेते।

बीजेपी विधायक धर्मेन्द्र मोची, गुरदीप सिंह और रामप्रताप कासनिया ने रीट मामले की सीबीआई जांच, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद करने और बेरोजगारों, किसानों के मुद्दों को लेकर स्लोगन लिखे बैनर का चोला पहनकर विधानसभा में एंट्री की।

दोनों लेवल रद्द हों : नारायण बेनीवाल

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल कहा कि पार्टी के तीनों विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर विरोध किया है। हमारी मांग है कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो और दोनों लेवल की परीक्षा रद्द हो। सरकार मान रही है कि रीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो जांच कराने में क्या ऐतराज है। सत्ता में बैठे किसी बड़े नेता का इसमें हाथ है। सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी है। हम पूरे बजट सत्र में यह कोशिश करेंगे कि युवाओं को न्याय मिले।

विधायक पुखराज गर्ग ने कहा रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा साथ में हुई। दोनों के पेपर शिक्षा संकुल में साथ थे। जिनके हाथ में परीक्षा के पेपर की जिम्मेदारी थी, वो अरेस्ट हुए हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हो गया। दूसरा लीक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पेपर लीक हुए हैं। परीक्षा रद्द करवाकर नए सिरे से वापस परीक्षा करानी चाहिए। ताकि ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। गरीब, किसान के बच्चों की नौकरी लगनी मुश्किल हो गई है।

राज्यपाल ने कोविड महामारी से निपटने में सरकार की सराहना की

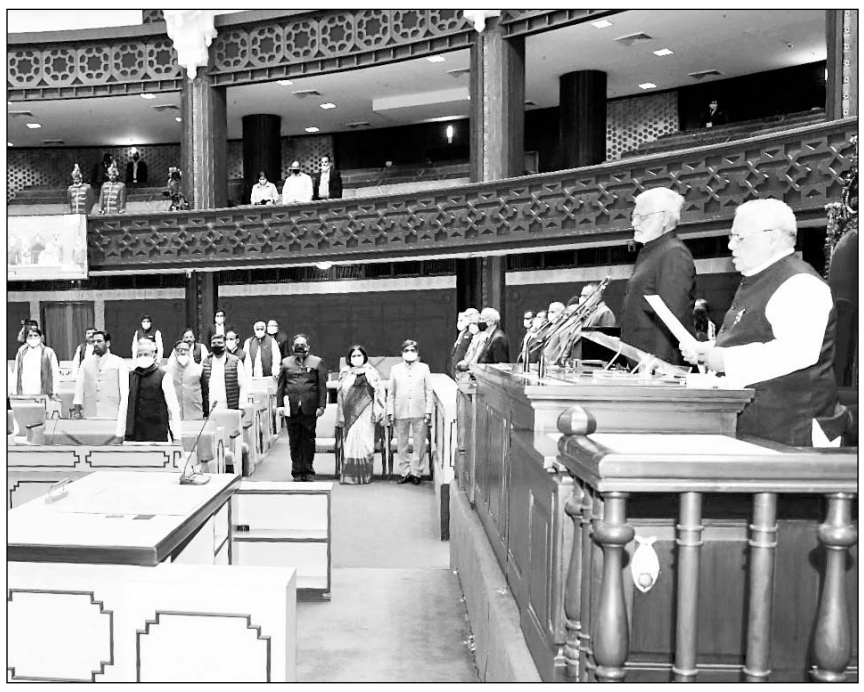

राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण से पहले बुधवार को विधानसभा में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया।

जयपुर (वि.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा के सातवें सत्र में आज अभिभाषण दिया। मिश्र ने कोरोना महामारी से निपटने में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों, गरीबों और जरुरमंदों के लिए खर्च करने में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी।

- राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
- 'वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।'

मिश्र ने कहा कि कोविड काल में जरुरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित लोगों का सर्वे कराया गया तथा जरुरतमंद 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए प्रति परिवार सहातार्थ दिए गए। जिससे राजकोष पर 1815 करोड़ रुपए का भार आया।

उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर का पैदल पलायन जब अन्य राज्यों से बड़ी समस्या बनकर उभरा तब हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंध किया। विशेष गाड़ियों और रेलों का खर्च राज्य सरकार ने उठाया। एक लाख 45 हजार टेस्ट प्रति दिन करने की क्षमता प्रतिदिन विकसित की गई। बेहतरीन करोना प्रबंधन से रिकवरी रेट बेहतर रही और मृत्यु दर भी नियंत्रण में रही। दवाइयों की उपलब्धता के लिए एयरक्राफ्ट तक का इस्तेमाल किया गया और आक्सीजन टेंकर की भी जीपीएस द्वारा मॉनिटरिंग करने जैसे नवाचार किए।

मिश्र ने कहा कि 40 हजार ऑक्सीजन कांस्ट्रेक्टर खरीदे तथा राजकीय चिकित्सालयों में 473 से अधिक आक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40 हजार आक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से एक हजार मैट्रिक टन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई हैं। राज्य में मात्र 5909 ऑक्सीजन बेड एवं 1211 आईसीयू बेड क्षमता उपलब्ध थी। जिससे बढ़ाकर 28 हजार ऑक्सीजन बेड और छह हजार आईसीयू बेड क्षमता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

राज्य में बजरी खनन में आ रही परेशानियों का हल न्यायिक प्रक्रिया से करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं जालोर में छह खनन पट्टों में खनन प्रारंभ किया जा चुका है तथा इस माह अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारंभ हो जायेगा। खनिज पदार्थों से होने वाली आय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में लगभग छह हजार 838 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा। हस्तशिल्प एवं कलाकृतियों के प्रोत्साहन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 5960 उद्यमियों को आयात निर्यात कोड जारी किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों में 29 हजार 444 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इसी तरह महत्वाकांक्षी रिफायनरी परियोजना के निर्माण पर अब तक 11 हजार 895 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि को बढ़ाने के साथ तीन लाख 53 हजार 915 आशार्थियों को 1305 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मिश्र ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। बेरोजगार युवाओं को 5175 डेयरी बूथ भी आवंटित किए गए।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में कुछ और वृद्धि हुई

राज्य में बुधवार को 3728 नए संक्रमित मिले, इससे पहले मंगलवार को 3479 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को भी नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। इस दौरान राज्य में 3728 नए मरीज मिले हैं। हालाकि राजधानी जयपुर में इनकी संख्या में कमी आई। इधर राज्य में 7 हजार से ज्यादा मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 34 हजार से कम रह गए है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 17 और लोगों की मौत हुई है।

राज्य में बुधवार को 249 मामले बढ़ने के साथ ही 3728 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले प्रदेश में 3479 रोगी पाए गए थे। इधर आज राजधानी जयपुर में नए संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है। इस दौरान जिले में 860 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 351, उदयपुर में 204, अलवर व गंगानगर में 188-188, कोटा में 187, सीकर में 146, राजसमंद में 118, झुंझुनूं में 112 और अजमेर में 103 नये मामले सामने आए है। वहीं प्रतापगढ़ में 98, नागौर में 94, बांसवाड़ा में 89, चूरू में 88, चितौड़गढ़ में 79, डूंगरपुर में 77, टोंक व भीलवाड़ा में 73-73, हनुमानगढ़ में 70, पाली में 66, सिरोही में 64, भरतपुर में 62, बारां में 53, सवाई माधोपुर में 51, जैसलमेर व झालावाड़ में 49-49, दौसा में 39, बूंदी में 30, बाड़मेर में 27, करौली में 24, बीकानेर में 9, धौलपुर में 4 और जालोर में 3 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच राज्य में 7177 मरीज ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस घटकर 33 हजार 812 रह गए है। इनमें सबसे ज्यादा 8867 रोगी जयपुर में हैं। प्रदेश में नए संक्रमितों की संख्या में कमी आने के साथ ही संक्रमण दर घटकर 7.90 फीसदी जबकि स्वस्थ दर बढ़कर 96.55 प्रतिशत हो गई है। उधर राज्य में करोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते बुधवार को प्रदेश में करोना से 17 और लोगों की मौत हुई है। इनमें जोधपुर में 4, जयपुर में 3, अजमेर व बूंदी में 2-2 जबकि भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक, सीकर और सिरोही में 1-1 मरीज की और मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9424 लोगों की मौत हो चुकी है।

- राजधानी जयपुर में थोड़ी कमी के बाद 860 नए संक्रमित मिले हैं।
- राज्य में 7 हजार से ज्यादा और मरीज ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 34 हजार से कम रह गए है।
- प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 17 लोगों की मौत हुई है।

जयपुर में 93 इलाकों में नए संक्रमित मिले

राजधानी में बुधवार को 93 इलाकों में नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 57 नए संक्रमित वैशाली नगर में पाए गए हैं। इसके अलावा बस्सी में 38, चाकसू में 35, झोटवाड़ा व फागी में 33-33, मानसरोवर व जमवारामगढ़ में 31-31, मुरलीपुरा में 22, जगतपुरा व मंगल विहार में 21-21, और आमेर में 20 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 17 ऐसे मरीज हैं जिनका नाम, पता व मोबाइल नम्बर गलत होने के कारण उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका। जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 1226 मरीज रिकवर हुए हैं।

वकीलों के कल्याण के लिए कल निकालेंगे शांति मार्च

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन और दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक के साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए मानदेय लागू करवाने के लिए 11 फरवरी को शांति मार्च निकाला जाएगा।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि तीनों मांगो को लेकर हजारों की संख्या में अधिवक्ता दोपहर साढ़े बारह बजे हाईकोर्ट परिसर से विधानसभा तक शांति मार्च करेंगे। अधिवक्ता लंबे समय से तीनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित अनेक अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं।

राजस्थान विधानसभा में लता व रावत को दी श्रद्धांजलि

जयपुर (वि.सं.)। विधानसभा में भारत रत्न एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ बिपिन रावत, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के निधन एवं बाड़मेर जिले की दुखान्तिका तथा गुवाहाटी- बीकानेर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के मृतकों के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुये आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पूर्व सांसद जमना देवी बारुपाल, गंगाराम कोली, श्याम सुन्दर सोमानी, बृजराज सिंह, डी. एन. पाटोदिया, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामचन्द्र जाट, पूर्व मंत्री जयनारायण पूनिया, महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान, कमलराम कोली, जीतमल जैन, रामकरण चौधरी, हीरालाल खांट, गोवर्धन सिंह और सूरजमल के निधन पर उन्हें विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने करने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इससे पहले जोशी ने शोक प्रस्ताव रखते हुए दिवंगत व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में दी गई सेवाओं की सराहना की।

पदोन्नति में भेदभाव क्यों?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग और कार्मिक विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक ही आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मियों को पदोन्नति देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश आरपीएस लोकेश सोनवाल की याचिका पर दिए।

नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी. पी. जोशी ने बुधवार को विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्य प्रीती शक्तावत तथा नगराज मीणा को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि विधानसभा उपचुनाव में प्रीती वल्लभनगर तथा नगराज मीणा धरियावाद से निर्वाचित हुए है।

डीसी सहित अन्य को भेजा जेल

जयपुर, (का.सं.)। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार जेडीए जोन- 4 की उपायुक्त ममता यादव और जेईएन श्याम मालू सहित सभी पांच आरोपियों को 21 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

राज्यपाल ने वापस लौटाया बाल विवाह रजिस्ट्रेशन का बिल

जयपुर, (वि.सं.)। राज्यपाल ने बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान वाले विवादित बिल को वापस लौटा दिया है। इस विवादित बिल को राज्यपाल ने बाल विवाह रोकने के कानून के खिलाफ बताते हुए इसमें संशोधन करने को कहा है। राज्यपाल के बिल लौटाने का लेटर विधानसभा को भेज दिया है। इस बिल में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी का भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान था।

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को पिछले साल 17 सितंबर को विधानसभा में पारित किया गया था। 24 सितंबर 2021 को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस बिल का सदन में भारी विरोध हुआ था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

बिवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन बिल 2021 में प्रावधान किया था कि अगर वर ने 21 साल और वधू ने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है तो उनके माता पिता या संरक्षक को शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन का आवेदन देने का प्रावधान किया था।

- राज्यपाल ने सरकार को लिखा "यह बिल बाल विवाह रोकने के प्रावधानों के खिलाफ, इसमें संशोधन करके भेजे"

गर्दन कटने के बाद भी मदद मांगने के लिए दौड़ा युवक, दर्दनाक मौत

जयपुर। वैशाली नगर गांधी पथ स्थित विवेक विहार में बुधवार सुबह करीब साढ़े दस बजे घर के अंदर चाकू से गर्दन कटने के बाद युवक मदद के लिए सड़क पर दौड़ने लगा। इस दौरान उसकी तड़पते हुए मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार घटना वैशाली नगर गांधी पथ स्थित विवेक विहार की है। जहां 40 वर्षीय राजू मंडल उर्फ फेंकन का घर में चाकू से गर्दन कट गई। इसके बाद वह खून में लथपथ होकर मदद के लिए घर से बाहर आकर दौड़ने लगा। इस दौरान वह सामने वाले घर में घुस गया। बाद में मकान से वापस बाहर सड़क पर आकर दौड़ने लगा और मदद मांगता रहा। कुछ देर बाद सड़क पर गिर गया। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। मदद मांगता रहा। कुछ देर बाद सड़क पर गिर गया। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। लोगों ने करणी विहार थाना पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देकर बुलाया। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय मकान में राजू के साथ पड़ोस के कमरे में रहने वाला किराएदार नंदू मौजूद था। पुलिस पड़ोसी किराएदार से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा कि युवक ने खुद गर्दन काटी या फिर अन्य किसी ने काटी। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का मामला होना प्रतीत हो रहा है।

राजस्थान में 44 निगम बोर्ड आयोगों में मिला नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षारत निगम-बोर्ड-आयोग में राजनीतिक नियुक्तियों की लंबी सूची सोश्यल मीडिया पर जारी हो गई है। जारी इस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों को भरपूर मौके मिले हैं। कांग्रेस के कई विधायकों सहित बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीयों को भी राजनीतिक नियुक्तियों में मौका मिला है। इसी के साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान को भी 20सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को भी राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दिया गया है। पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत को भी राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दिया गया है। निगम-बोर्ड-आयोगों में हुई इन राजनीतिक नियुक्तियों में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अधिकांश लोग दरकिनार कर दिए गए हैं और दो-तीन लोगों को छोड़ दें तो सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चली है।

सोशल मीडिया में जारी सूची के अनुसार डॉ. चन्द्रभान (उपाध्यक्ष), बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, रामेश्वर डूडी, राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड, महादेव सिंह खण्डेला (अध्यक्ष) को दीपचंद खैरिया (उपाध्यक्ष), राजस्थान किसान आयोग, बृजकिशोर शर्मा (अध्यक्ष), पंकज मेहता (उपाध्यक्ष), राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जुबेर खान, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, धीरज गुर्जर, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि., रफीक खान, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, खिलाड़ीलाल बैरवा (अध्यक्ष), सचिन सर्वटे (उपाध्यक्ष), राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, मेवाराम जैन (अध्यक्ष), सुमेर सिंह राजपुरोहित (उपाध्यक्ष), राजस्थान गौ सेवा आयोग, हाकम अली खान, राजस्थान वक्फ विकास परिषद, डूंगरराम गैदर (उपाध्यक्ष), शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, लाखनसिंह मीणा, डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल, जोगिन्द्र सिंह अवाना, देव नारायण बोर्ड, कृष्णा पूनिया (अध्यक्ष), सतबीर चौधरी (उपाध्यक्ष), राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, धर्मेन्द्र सिंह राठौड़, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, पुखराज पाराशर, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जस्टिस भंवरू खान, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रेहाना रियाज चिश्ती, राजस्थान राज्य महिला आयोग, गोपालसिंह शेखावत (अध्यक्ष), राजेश टंडन (उपाध्यक्ष), वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड, मानवेन्द्र सिंह जसौल (अध्यक्ष), रामकिशोर बाजिया (उपाध्यक्ष), राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, लक्ष्मण सिंह रावत, मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल, के.सी.बिश्नोई, राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (अध्यक्ष), सांवरमल महरिया (उपाध्यक्ष), राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण, राजेन्द्र सिंह सोलंकी (अध्यक्ष), चुन्नीलाल राजपुरोहित (उपाध्यक्ष), राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड, राजीव अरोड़ा, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, संदीप चौधरी, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, उमाशंकर शर्मा, आयुक्त, राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग, किशनलाल जैदिया (उपाध्यक्ष), राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, लक्ष्मण मीणा (अध्यक्ष), रमीला खड़िया (उपाध्यक्ष), राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग, महेन्द्र गहलोत (अध्यक्ष), केश कला बोर्ड, सीताराम लाम्बा (अध्यक्ष), सुशील पारीक (उपाध्यक्ष), राजस्थान युवा बोर्ड, उर्मिला योगी (अध्यक्ष), चतराराम देशबंधु (उपाध्यक्ष), राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड, अनिल शर्मा, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल, रामसिंह राव, वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी, जगदीशराज श्रीमाली (उपाध्यक्ष), श्रम सलाहकार समिति, रमेश बोराणा (उपाध्यक्ष), राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, लक्ष्मण कड़वासरा, भूदान यज्ञ बोर्ड, मदन गोपाल मेघवाल, डॉ.भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), भैरूलाल गुर्जर, सांवलिया मंदिर ट्रस्ट, महेश शर्मा (अध्यक्ष), मंजू शर्मा (उपाध्यक्ष), विप्र कल्याण बोर्ड, मुमताज मसीह (अध्यक्ष), मानसिंह गुर्जर (उपाध्यक्ष), सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ वॉलंट्री सैक्टर, शंकर यादव, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन, पवन गोदारा, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन व कीर्ति सिंह भील (उपाध्यक्ष), मारवाड़ा क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड बनाया है।

- सोश्यल मीडिया पर जारी सूची में सचिन पायलट के लोग हुए दरकिनार, गहलोत खेमे को मिला फायदा

पदोन्नति में भेदभाव क्यों?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग और कार्मिक विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक ही आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मियों को पदोन्नति देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश आरपीएस लोकेश सोनवाल की याचिका पर दिए।

जब पूरा विपक्ष रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर एकजुट था, तब वसुंधरा-गहलोत हंसी-मजाक में मशगूल थे

जयपुर (कासं)। विधानसभा में बुधवार को जब पूरा विपक्ष रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर एकजुट था, तब पूरे प्रदेश की जनता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को हंसी-मजाक करते हुए देख रही थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब-जब भाजपा, गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रामक होती है तो वसुंधरा राजे को यह रास नहीं आता, ऐसा ही उन्होंने विधानसभा सत्र के पहले दिन भी किया।

चर्चा है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां के नेतृत्व में सभी बीजेपी विधायक हाथ में काली पट्टी बांधकर और तख्तियां लिये सरकार के विरोध में खड़े हुए, तब एकबारगी तो वसुंधरा राजे को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हंसी-मजाक कर रीट मामले से ध्यान भटकाने की असफल कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ पूरा विपक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती से लडाई लड़ने को तैयार खड़ा था। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की हंसी-मजाक का नजारा विधानसभा के यू-ट्यूब प्रसारण पर पूरे प्रदेश की जनता ने भी देखा।

सूत्रों के मुताबिक 8 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में जब भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, तब वहां भाजपा के सभी विधायक रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुये हमले, किसान कर्जमाफी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने को एकजुट दिखे। इसके बावजूद यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचरण सराफ और अशोक लाहोटी का आचरण यह सिद्ध करता है कि वह चाहते हैं कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह विभाजित दिखे, लेकिन गुलाबचंद कटारिया, राजेन्द्र राठौड़ और सतीश पूनियां के रणनीतिक कौशल व इनके साथ 65 से अधिक विधायकों के साथ होने से वसुंधरा राजे भाजपा को सड़क से लेकर विधानसभा तक विभाजित करने में विफल साबित हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि, महात्मा गांधी सर्किल पर भाजपा विधायकों के धरने में भी राजे को मजबूरी में आना पड़ा था, क्योंकि सभी विधायक विधानसभा से सीधे धरने में पहुंच चुके थे, इनको अब यह लगता था कि गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में किए जा रहे धरने पर विधायक नहीं आएंगे, लेकिन बावजूद वहां लगभग सभी विधायक पहुंचे, जो कि विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे, तब लगभग 1 घंटे बाद मुंह छुपाने के लिए वसुंधरा राजे और इन तीन विधायकों को मजबूरी में शायद वहां आना पड़ा। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि, सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे की कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या भूमिका है, अलबत्ता तो विपक्ष के नाते सरकार और अशोक गहलोत के विरुद्ध धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आती, ट्विटर पर भी कभी-कभी अपनी सहूलियत के कारण मजबूरी में आती हैं।

गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक में 8 फरवरी को वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का यह बयान पार्टी के लिए कितना खतरनाक है कि "बारां में सांसद कार्यालय पर पत्थरबाजी नहीं होती तो आप पर भी (सतीश पूनिया) जानलेवा हमला नहीं होता।" सिंघवी के इस बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि, हमले के षडयंत्र में कांग्रेस का समर्थन करने में वसुंधरा राजे की सियासी चाल भी हो सकती है।